**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2144**

**उत्तर देने की तारीखः 12**.0**5**.2016

**कोठारी आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन**

**2144. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय कम हो गया है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किए गए बजटीय आवंटन में इस वर्ष भारी कटौती की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या बजट में की गई कमी के कारण यू॰जी॰सी॰ द्वारा प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति पर असर पड़ेगा?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): प्रो. डी.एस. कोठारी की अध्‍यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66) का गठन किया गया था। इसे देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देने का दायित्‍व सौंपा गया था। इस आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1968 में अपनाई गई राष्‍ट्रीय नीति का आधार बनी। इसने निरक्षरता का उन्‍मूलन; 10+2+3 का एकसमान शिक्षा ढांचा; माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण; दस वर्ष की स्‍कूलिंग के दौरान गणित और विज्ञान का अनिवार्य शिक्षण; त्रिभाषा फार्मूला; दूरस्‍थ और अंशकालिक शिक्षा के साथ-साथ उच्‍च शिक्षा की सुविधाओं का विस्‍तार; उत्‍कृष्‍टता केंद्रों को प्रोत्‍साहन; और शिक्षा पर व्‍यय को बढ़ाकर राष्‍ट्रीय आय का छह प्रतिशत तक करने जैसे अनेक दूरगामी सुधारों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों में से कई को कार्यान्‍वित कर दिया गया है।**

**कोठारी आयोग ने जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्‍यय करने की सिफारिश की थी और वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 198**6 **में** **भी यह** **निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर निवेश को उत्‍तरोत्‍तर बढ़ाकर राष्‍ट्रीय आय के 6% तक पहुंचाया जाए। वर्ष 2011-12, 2012-13 (संशोधित अनुमान) और 2013-14 (बजट अनुमान) के दौरान शिक्षा पर व्‍यय जीडीपी का क्रमश: 3.99%, 4.35% और 4.44% है। अत: यह स्‍पष्‍ट है कि सरकार शिक्षा में अधिक निवेश की ओर अग्रसर है।**

**वर्तमान में, सरकार नई शिक्षा नीति (एनईपी) बना रही है, जिसके लिए सरकार ने 33 प्रकरणों पर ऑनलाइन, राज्‍यों के माध्‍यम से जमीनी स्‍तर पर और प्रकरणगत विचार-विमर्श आयोजित किया था। जिसमें शिक्षण-अधिगम की पहुंच, समावेशिता और गुणवत्‍ता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम, छात्र सहायता और शिक्षा का वित्‍तपोषण आदि से संबंधित विभिन्‍न मामलों को कवर किया गया था। इन बहु-परामर्शों के माध्‍यम से प्राप्‍त सभी सुझावों को राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए गठित नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति को भेज दिया गया है।**

**(ग) और** (**घ): जी, नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए यूजीसी का बजटीय आवंटन योजना के अंतर्गत 1845 करोड़ रुपए और योजनेतर के अंतर्गत 2441.94 करोड़ रुपए है। वर्ष 2015-16 के लिए, बजट अनुमान स्‍तर पर बजटीय आवंटन योजना के अंतर्गत 1665 करोड़ रुपए और योजनेतर के अंतर्गत 2135.96 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमान स्‍तर पर योजना के अंतर्गत 1515 करोड़ रुपए एवं योजनेतर के अंतर्गत 2135.96 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016-17 के दौरान बजटीय आवंटन से यूजीसी अपनी अध्‍येतावृत्‍तियों और छात्रवृत्‍तियों का वितरण कर सकेगा।**

**\*\*\*\*\***